

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 46/21

GCMS NO 2021/140

1. वीरेन्द्र सिंह
 2. राजवीर
 3. चन्द्रवीर
 4. तेजवीर पिसरान साहब सिंह जातियान जाट निवासीयान श्यारौली तहसील वजीरपुर
 5. सन्तो देवी बेवा साहब सिंह जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर
- अपीलांत



बनाम

1. धारा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
 2. भगवान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जातियान जाट निवासीयान श्यारौली तहसील वजीरपुर
- रेसपो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 97/20 निर्णय दिनांक 11.2.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, वजीरपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रेसपो श्री अभय गुप्ता

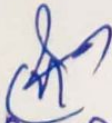
दिनांक 26.3.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.2.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, वजीरपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलाटगण के पिता साहब सिंह पुत्र अर्जुन सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 1594 रकबा 1.46 है0 ग्राम श्यारौली मे स्थित है। जिसमे सायल एवं गैरसायल काबिज चले आ रहे है। सायल एवं गैरसायल ने उक्त भूमि का रोड साईड से मौखिक बंटवारा कर रखा है तथा आपसी सहमति से ही सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ने उक्त भूमि मे अपने भूमि विकास के लिए एवं आवास के लिए मकान बना रखे है। दोनो गैरसायलान द्वारा साज कर लिया है तथा रोड साईड की की समस्त अच्छी किरम की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जबकि गैरसायल को इस प्रकार से अच्छी किरम की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। गैरसायलान द्वारा दिनांक 21. 7.20 को सालय को धमकी दी है कि वो दोनो रोड साईड की अच्छी किरम की भूमि पर कब्जा करेगे तथा तुम्हे रोड के पीछे की भूमि देगे तथा उन्होने रोड साईड की पूरी भूमि पर सायल को पुख्ता निर्माण करने की भी धमकी दी। गैरसायलान अपनी बेजा हरकतो से तब तक बाज नही आवेगे जब तक कि उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि सायल की रोड साईड की भूमि पर कोई अवैध निर्माण नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलाटगण के पिता साहब सिंह द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा





राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सायल/अपीलांटगण के पिता का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर सायल के वारिसान/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश परवर्स, आर्बीट्रेरी एवं विधि के मध्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलार्थी सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने एवं गैरसायलान द्वारा पेश काउन्टर टी आई अस्वीकार किये जाने योग्य है। सायल (अपीलार्थी के पिता/पति) ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मद न० 3 में स्पष्टतः यह उल्लेखित किया है कि सायल व गैरसायल ने वादग्रस्त भूमि का रोड साईड से मौखिक बंटवारा कर रखा है तथा आपसी सहमति से सायल व गैरसायल संख्या 1 ने उक्त भूमि में अपने भूमि विकास के लिए आवास के लिए मकान बना रखे हैं। इस तरह से सायल ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र टी आई में यह कही भी अंकित नहीं किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि ख०न० 1594 में से रोड साईड की भूमि का कोई हिस्सा या भाग सायल के हिस्से में नहीं आया, बल्कि सायल ने तो स्पष्टतः यह अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ख०न० 1594 में से रोड साईड की भूमि व पीछे की भूमि दोनों में ही तीनों भाईयों का समान रूप से हिस्सा है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सायल के प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कथनों पर कतई गौर एवं विश्वास नहीं कर केवल मात्र गैरसायलान के मिथ्या कथनों पर गौर एवं विश्वास कर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर भारी कानूनी भूल की है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारों के पिता के समय खरीदी हुई भूमि है एवं शुरू से ही उक्त भूमि ओन रोड स्थित है अर्थात् उक्त भूमि शुरू से ही रोड के लंगवा है। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति शामिल भूमि जो कि रोड के लंगवा स्थित हो उसका विभाजन करने में वह रोड के लंगवा भूमि जो कि हर समयानुसार मूल्यवान ही होती है चाहे वर्तमान समय में उसका मूल्य आंका जाये या वर्तमान में सालों पहले उसका मूल्य आंका जावे। लिहाजा स्वाभाविक रूप से कोई भी सहखातेदार इस प्रकार की वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने में अपने मूल्यवान रोड साईड की भूमि को क्यों नहीं लेना चाहेगा। वह रोड साईड की अच्छी किस्म व मूल्यवान किस्म की अपनी भूमि के हिस्से व हक को छोड़कर कम मूल्य की भूमि ही क्यों लेगा। सामान्य रूप से भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। सायल ने प्रार्थना पत्र में रोड साईड की भूमि उसका हिस्सा सहखातेदारी व कब्जा होने का कथन किया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र गैरसायलान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में इस बाबत वर्णित मिथ्या बनावटी कथनों को मूलवाद में बिना उभयपक्षों की साक्ष्य रिकार्ड हुये ही सही मानकर एवं यह मानकर कि रोड साईड की भूमि का कोई भाग सायल के हिस्से व खातेदारी का नहीं है। आलौच्य आदेश पारित कर भारी ताथ्यिक एवं कानूनी भूल की है। सायल ने यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय में रखा है कि रोड साईड की भूमि तीनों भाईयों सायल व गैरसायलान ने अपना हिस्सा बराबर रखा है। गैरसायल संख्या 1 ने रोड की तरफ अपने हिस्से


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

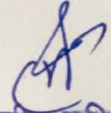
मे कुछ भूमि मे छोटा सा आवासीय मकान बना रखा है तथा सायल का रोड साईड की भूमि का हिस्सा सायल ने खाली रख रखा है। लेकिन गैरसायल की नियत अब खराब हो वे आपस मे मिलकर रोड साईड की सम्पूर्ण भूमि अर्थात सायल के हिस्से की भूमि सहित अकेले ही कब्जा करना चाहते है एवं उसमे निर्माण करने की सायल को धमकी दी गई। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। चूकि रोड साईड की भूमि मे सायल व गैरसायलान का बराबर बराबर हिस्सा है। इसलिए सायल ने उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का सरस नरस से मीटस एण्ड बाउण्डस से अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी दोनो तरह की भूमि का तीनो भाईयो ने रिकार्डेड विभाजन करने हेतु यह दावा गैरसायलान के विरुद्ध सायल का वादकारण उत्पन्न होने पर दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया है। जिसका निर्णय उभयपक्षो की साक्ष्य रिकार्ड किये जाने के उपरान्त ही विधि सम्मत किया जा सकता है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र टी आई के निस्तारण की स्टेज पर ही यह मानकर कि पक्षकारो मे वादग्रस्त भूमि का विभाजन हो चुका है मूल दावे का परोक्ष रूप से निर्णय कर दिया है एवं इस तरह से फाईडिंग देकर आलोच्य आदेश पारित कर सायल के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर कानूनी भूल की है। सायल व गैरसायल द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र टी आई जबाब मय काउन्टर टी आई मे अंकित कथनो व तथ्यो की सत्यता को मूल वाद मे उभयपक्षो की साक्ष्य रिकार्ड पर करने के उपरान्त ही निर्णायक रूप से नियमानुसार व विधि अनुसार किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र टी आई की स्टेज पर तो न्यायालय को सिर्फ प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ पर विवेचन कर प्रार्थना पत्र का कानूनन निस्तारण किया जाना चाहिए था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानो को कतई नजर अंदाज कर आलोच्य आदेश मे मात्र यह मानकर कि सायल व गैरसायलान मे भूमि का मौखिक विभाजन लम्बे समय पूर्व हो चुका है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र टी आई व काउन्टर टी आई दोनो मे से किसी के भी पक्ष मे निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। सायल का प्रार्थना पत्र टी आई खारिज कर भारी कानूनी व ताथ्यिक भूल की है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त फाईडिंग की परिपेक्ष्य मे यह स्थिति साफ है कि वास्तविकता मे अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य आदेश से पक्षकारो मे कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न होने एवं उसमे आपस मे झगडा होने शांति भंग होने की पूर्ण संभावना बन गई है। क्योकि एक और सायल ने रोड साईड की भूमि मे अपना बराबर का हिस्सा व कब्जा होना तथा गैरसायलान द्वारा जबरदस्ती उसके हिस्से की भूमि पर कब्जा करने व निर्माण करने पर आमदा होने का कथन किया है वही इसके विपरीत गैरसायलान ने रोड साईड की सम्पूर्ण भूमि पर सायल का कोई हिस्सा नही होना व उसका कब्जा नही होना तथा उन्ही का कब्जा होने का कथन किया है। ऐसे मे कब्जे व हिस्से को लेकर पक्षकारो के मध्य मौजूद उक्त विवाद बिन्दुओ का निस्तारण तो उभयपक्षो को साक्ष्य उपरान्त ही तय किया जाना विधि सम्मत है एवं मूल वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पक्षकारो मे उपजे विवादो को मूल वाद के निस्तारण तक रोकने के लिए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है। विधि का सुस्थापित



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सिद्धान्त है कि टी आई की स्टेज पर ही दावे का निस्तारण जैसा आदेश प्रार्थना पत्र के निर्णय के समय किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक सिद्धान्त की अनदेखी कर भारी कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांतों के प्रावधानों पर गौर नहीं किया है ना ही उनका हवाला अपने निर्णय में दिया है। आलोच्य आदेश पारित होते समय अपीलान्त के पिता/पति जीवित ही नहीं था। कानूनी स्थिति यह है कि प्रकरण के किसी भी मृत पक्षकार के पक्ष या विपक्ष में कोई भी आदेश/निर्णय नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलार्थी तत्समय अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाये गये इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की कोई जानकारी समय पर नहीं हुई तथा इसी बीच कोविड 19 की लहर फैल जाने से लॉकडाउन लग गया एवं न्यायालय बंद हो गये। इसी का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पो0 ने दिनांक 20.6.21 को उक्त वादग्रस्त भूमि में रोड साईड की अपीलार्थी के कब्जे व हिस्से की भूमि में जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से पुख्ता निर्माण करना शुरू कर दिया तब अपीलार्थीगण ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने ऐलानिया अपीलार्थीगण से कहा कि तुम्हारी टी आई खारिज हो चुकी है हमें कोर्ट ने पाबन्द नहीं किया है तुमने निर्माण कार्य में बाधा डाली तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। तब जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी की गई जानकारी होने पर अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की जा रही है कानूनगी पैचीदगियो से बचने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 का काउन्टर टी आई खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा न0 1594 रकबा 1.46 है0 अपीलान्त/सायल व गैरसायल/रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य करीब 30 वर्ष पहले की सायल एवं गैरसायलान के पिता अर्जुन सिंह के समय ही बंटवारा हो गया था। उस समय सड़के किनारे की जमीन पर खेती में मवेशियों व राहगीरों द्वारा नुकसान पहुँचा दिया जाता था इस कारण सायल/अपीलान्त के पिता ने अपनी इच्छा से उक्त जमीन का उत्तरी पूर्वी 1/3 हिस्सा लिया। इसी तरह गैरसायल संख्या 2 के हिस्से में उक्त जमीन का दक्षिणी हिस्सा आया तथा गैरसायल संख्या 1 के हिस्से में उक्त जमीन का पूर्वी हिस्सा आया। तभी से सायल व गैरसायलान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काशत कर रहे हैं तथा तीनों हिस्सेदारों ने डोल मेड बनाकर अपने अपने हिस्से पर काशत हो रही है। गैरसायल संख्या 1 ने अपने हिस्से की जमीन को विकसित करने के लिए लाखों रुपये खर्च किये हैं तथा खेती की सुरक्षा के लिए मकान भी बना रखा है। गैरसायल संख्या 2 ने भी अपने हिस्से में एक दुकान नुमा का निर्माण कर रखा है। तीनों हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से की जमीन को काफी लम्बे समय से काशत करते चले आ रहे हैं। एक दुसरे का एक दुसरे की जमीन से किसी प्रकार का कोई मौके पर किसी तरह का संबंध नहीं है। मौके पर अपीलान्त/सायल का गैरसायलान के हिस्से में आई जमीन से ज्यादा हिस्सा है। गैरसायलान/रेस्पो0 ने कोई साज नहीं कर रखी है ना ही अपीलान्त की भूमि पर कब्जा


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करना चाहते हैं। पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे के समय अच्छी जमीन अपीलांट ने स्वयं प्राप्त की है। इस प्रकार रेस्पो/गैरसायलान द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सालय के पक्ष में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सुतलन सिद्ध नहीं होने एवं किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति नहीं होने के कारण ही विधि के अनुसार खारिज किया है जो विधि के प्रावधानों के तहत है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पुत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर अपीलांट के कथन अनुसार करीब 30 वर्ष पूर्व ही उनके पिता अर्जुन सिंह के समय ही बंटवारा हो चुका है। बंटवारे में हिस्से में आई भूमि अनुसार ही पक्षकारान मौके पर काबिज काशत है। चूंकि बंटवारे के समय विवादित आराजीयात की भूमि की दरे काफी कम थी वर्तमान समय में भूमि की दरो के बढ़ोतरी होने के कारण विवादित उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होना पक्षकारों से स्वीकृत किया है। विवादित आराजीयात के बाबत सायल/अपीलांट के पिता द्वारा गैरसायलान/रेस्पो0 को पाबन्द कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई थी इसी प्रकार गैरसायलान/रेस्पो0 द्वारा काउन्टर टी आई प्रस्तुत कर सायल/अपीलांट को पाबन्द कराने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट के पिता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज किया है तथा गैरसायलान का काउन्टर टी आई प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार का निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसके बंटवारे के बाबत दावा अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के मध्य वाद वाहुलता नहीं बढ़े इसलिए उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर के प्रकरण संख्या 97/20 में पारित निर्णय दिनांक 11.2.21 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्षों को ताफैसला दावा इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात ख0न0 1594 रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम श्यारौली तहसील वजीरपुर की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर प्राधिकारी